MKLIVE

योजनाओं के प्रकार

केंद्रीय क्षेत्रक योजना

100 प्रतिशत वित्तपोषण केंद्र सरकार द्वारा; कार्यान्वयन भी केंद्र द्वारा; मुख्यतः संघ सूची में उल्लिखित विषयों से संबंधित योजनाएं

केंद्र प्रायोजित योजनाएं

राज्यों को योजनाओं के कार्यान्वयन में केंद्र द्वारा वित्तीय सहायता; मुख्यतः समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों से संबंधित योजनाएं

राज्य सरकारों की योजनाएं

पूर्णतः राज्यों द्वारा निर्मित एवं क्रियान्वित योजनाएं; मुख्यतः राज्य सूची में उल्लिखित विषयों से संबंधित योजनाएं

स्मार्ट कार्यक्रम

- कब : 2023
- किसने : राष्ट्रीय आयोग और केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद
- उद्देश्य : देश में आयुर्वेद में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य आयुर्वेद कॉलेजों और अस्पतालों के माध्यम से आयरन की कमी वाले एनीमिया, मोटापा जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल अनुसंधान क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना है।
- यह शिक्षकों को स्वास्थ्य अनुसंधान के निर्धारित क्षेत्रों में परियोजनाओं को शुरू करने और एक बड़ा डेटाबेस तैयार करने के लिए प्रेरित करेगा।

भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग

- यह भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020 द्वारा आयुष मंत्रालय के तहत स्थापित एक वैधानिक संस्था है। इसका उद्देश्य चिकित्सा शिक्षा को विनियमित करना है ।
- यह गुणवत्तापूर्ण और वहनीय चिकित्सा शिक्षा तक पहुंच में सुधार करने की दिशा में कार्य करता है। साथ ही यह देश के सभी हिस्सों में भारतीय चिकित्सा प्रणाली के पर्याप्त और उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है।

भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना

- कब : 2023
- किसने : नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NTPC) तथा गुजरात गैस लिमिटेड (GGL) द्वारा संयुक्त रूप से
- कहां : गुजरात के सूरत जिले के आदित्य नगर के 'कवास' नामक गांव में
- NTPC की ओर से जारी आधिकारिक बयान के अनुसार विनियामक संस्था पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (PNGRB) ने PNG के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के 5% मिश्रण के लिए मंजूरी दे दी है। निकट भविष्य में हाइड्रोजन मिश्रण 20% तक पहुंचाया जाएगा।

यह उपलब्धि केवल ब्रिटेन, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे कुछ गिने-चुने देशों द्वारा प्राप्त की गई है। यह परियोजना भारत को वैश्विक हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के केंद्र में लाएगी। भारत इससे न केवल अपने हाइड्रोकार्बन आयात बिल को कम करेगा बल्कि विश्व में हरित हाइड्रोजन और हरित रसायन निर्यातक बनकर विदेशी मुद्रा अर्जित करेगा।

NTPC की ओर से जारी आधिकारिक बयान

- हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना का उपयोग ऊर्जा के क्षेत्र में नवीन और उभरते हुए विकल्पों की खोज करने की दिशा में सहायक सिद्ध होगा।
- PNG के साथ हाइड्रोजन के मिश्रण से कार्बन का उत्सर्जन अपेक्षाकृत कम

राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन

- कब : 2023
- किसने : केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
- उद्देश्य : भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और इसके सहायक उत्पादों के उत्पादन, उपयोग तथा निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना
- साथ ही इस मिशन का उद्देश्य वर्ष 2030 तक भारत में लगभग 125 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकसित करने के साथ-साथ प्रतिवर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास करना भी है।
- इसके अलावा इस मिशन के अंतर्गत 8 लाख करोड़ रूपए से अधिक के निवेश के माध्यम से लगभग 6 लाख रोजगार के अवसर सृजित करने के लक्ष्य की भी परिकल्पना की गई है।
- यह मिशन औद्योगिक, परिवहन और ऊर्जा क्षेत्रों का डीकार्बोनाइज़ेशन आयातित जीवाश्म ईंधन एवं फीडस्टॉक पर निर्भरता कम करने, घरेलू विनिर्माण क्षमता बढ़ाने, रोज़गार की संभावनाएँ पैदा करने तथा नई प्रौद्योगिकियों के विकास का पथ भी प्रशस्त करेगा।
- इस मिशन के फलस्वरूप जीवाश्म ईंधन के आयात में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की शुद्ध कमी के साथ ही वार्षिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 50 मीट्रिक टन की कमी आएगी।

ई-सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स प्रोजेक्ट **(eSCR)**

- एक डिजिटल प्लेटफार्म
- कब : 2023
- किसने : सुप्रीम कोर्ट
- उद्देश्य : कीलों, विधि के छात्रों एवं सामान्य लोगों को सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को निःशुल्क उपलब्ध कराना

- eSCR में 26 जनवरी, 2023 से सुप्रीम कोर्ट के लगभग 1300 से अधिक निर्णयों को हिंदी सहित संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित 13 अनुसूचित भाषाओं में अपलोड

भारत प्रवाह पहल

- कब : 2023
- किसने : पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय
- उद्देश्य : साहित्य, संवाद एवं संचार के माध्यम से जनसाधारण के रोजमर्रा के जीवन में नदियों-बंदरगाहों एवं नौवहन की भूमिका को प्रदर्शित करना

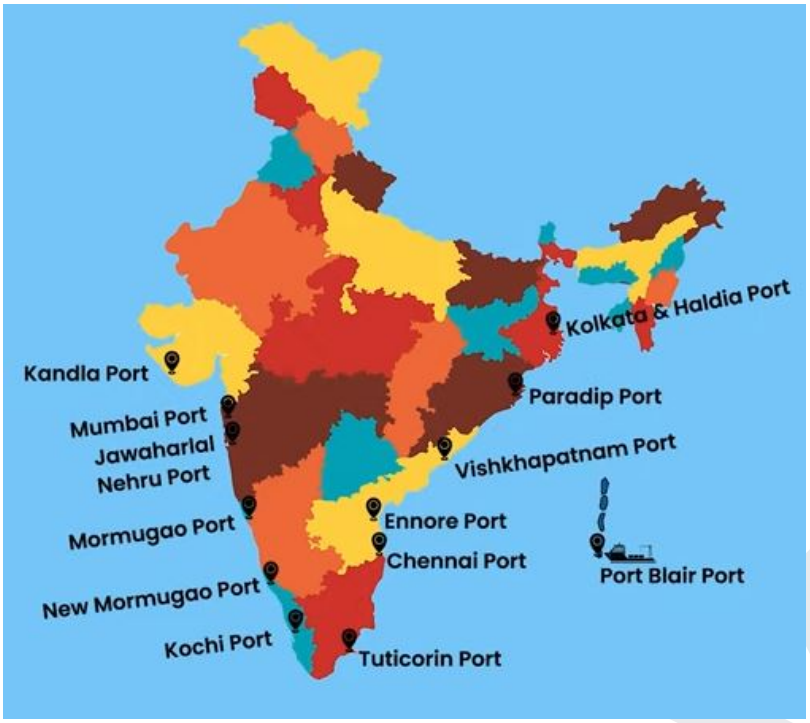

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना

- कब : 2023
- किसने : केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
- उद्देश्य : पारंपरिक शिल्पकारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना
- पारंपरिक कारीगरों व दस्तकारों जैसे बढ़ई, दर्जी, टोकरी बनाने वाले, नाई , सुनार लोहार, कुम्हार, हलवाई ,मोची आदि मजदूरों को छोटे उद्योग स्थापित करने के लिए 10 हजार से लेकर 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता + ट्रेनिंग
- इस योजना के माध्यम से उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा + सरकार द्वारा इन कारीगरों के उत्पादों को अच्छा मूल्य दिलाया जाएगा

पात्रता

- नागरिकता
- केवल विश्वकर्मा समुदाय के नागरिक पात्र → जाति प्रमाण पत्र
- आवेदक पारंपरिक कारीगर एवं शिल्पकार होना चाहिए
- आवेदन करने हेतु आयु सीमा निर्धारित नहीं

- इस योजना के माध्यम से अलग-अलग पारंपरिक कौशल को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके लिये उन्हें ट्रेनिंग और फंडिंग प्रदान करने के साथ ही तकनीकी सुविधाओं से भी लाभान्वित किया जाएगा।

दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक गलियारा परियोजना

- 2023 में प्रधानमंत्री ने गति शक्ति योजना के तहत दक्षिण भारत के पहली औद्योगिक गलियारा परियोजना की शुरूआत की है। इस परियोजना का नाम चेन्नई-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा है। प्रधानमंत्री ने इसी औद्योगिक गलियारा के एक हिस्से के रूप में तुमकुरु औद्योगिक टाउनशिप का उद्घाटन किया है।
- तुमकुरु औद्योगिक टाउनशिप मंगलुरु बंदरगाह से 300 किमी की दूरी पर स्थित है। यह ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट को अपनाता है।

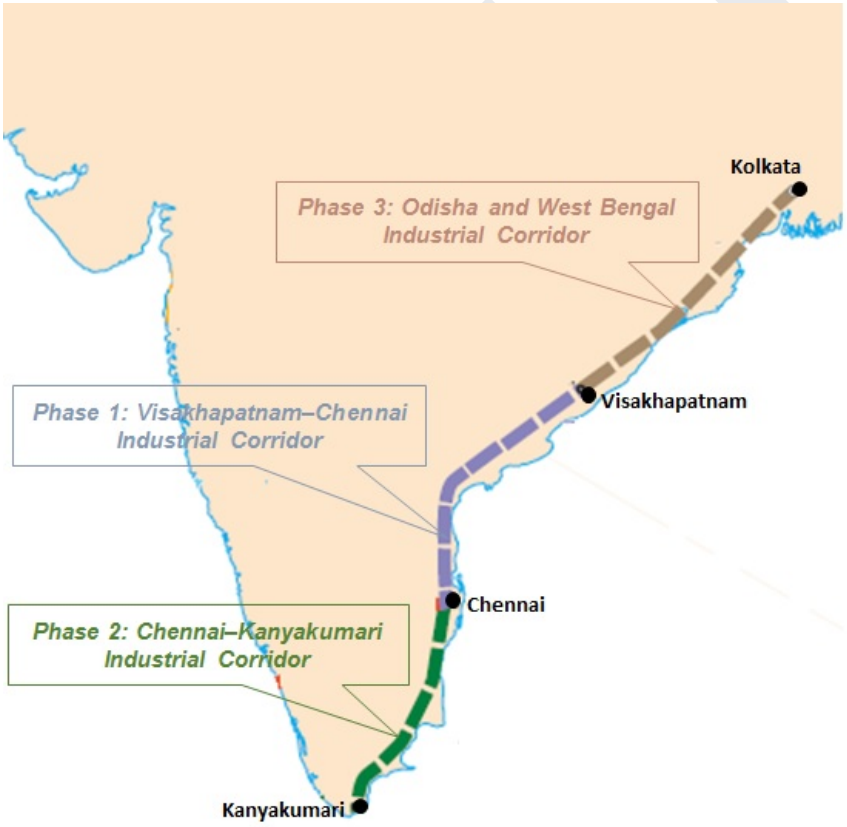

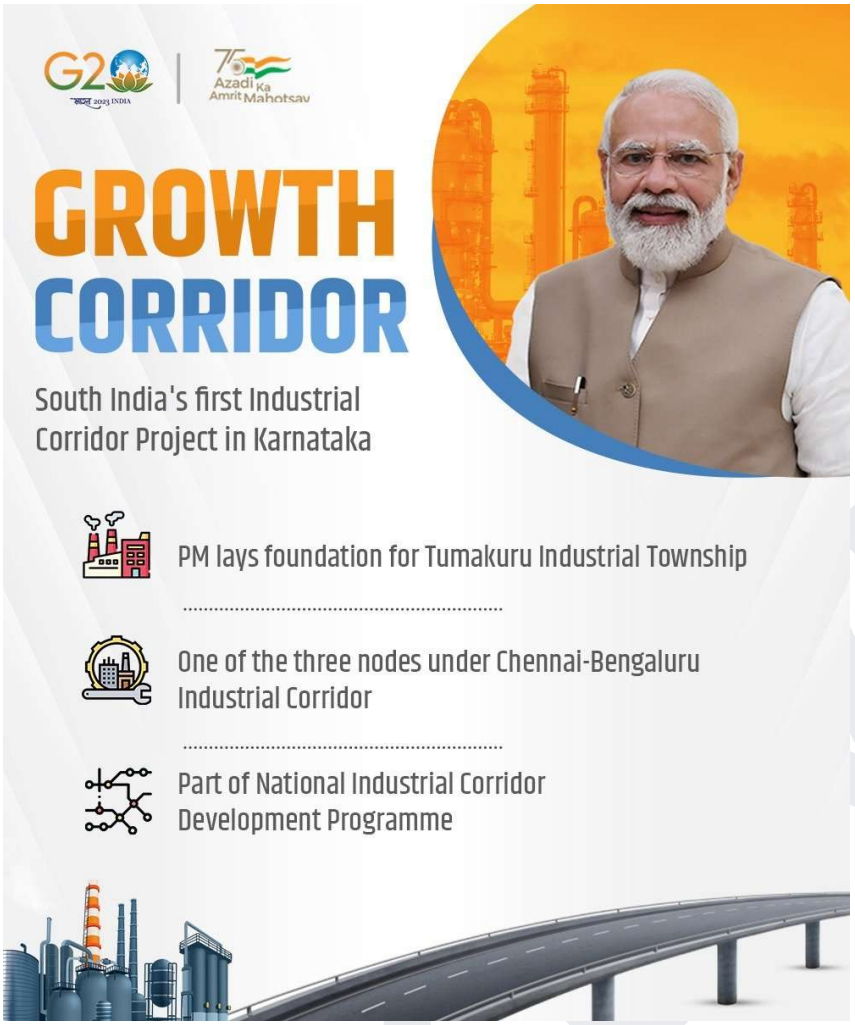

महत्व

- दक्षिण भारत में पहला औद्योगिक गलियारा
- 88,000 से अधिक रोजगार
- 7,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित
- समावेशी विकास में योगदान
- आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों के अनुरूप
- यह परियोजना खाद्य उत्पादों, परिधान, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग और रसायनों पर ध्यान केंद्रित करेगी। यह भारत सरकार के मंत्र Reform, Perform, and Transform के अनुरूप है।

प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना

- कब : 2021

- केंद्र सरकार के 16 मंत्रालयों को जोड़ने वाला एक डिजिटल मंच
- रेलवे, सड़क एवं परिवहन, ऊर्जा, पेट्रोलियम, नागरिक उड्डयन जैसे मंत्रालय
- 100 लाख करोड़ रूपये का वित्त स्वीकृत

मूल लक्ष्य

- भारत में आधारभूत संरचनाओं के विकास को गति प्रदान करना
- विभिन्न मंत्रालयों की विभिन्न आधारभूत परियोजनाओं को एक अंब्रेला परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित करना
- परियोजनाओं के क्रियान्वयन में परस्पर समन्वय स्थापित करना
- इन 16 मंत्रालयों के तहत संचालित हो रही परियोजनाओं को प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के दायरे में सम्मिलित कर दिया जाएगा, ताकि इन योजनाओं को यथाशीघ्र पूरा किया जा सके।

उपलक्ष्य

- योजना के तहत सम्मिलित योजनाओं को 2024-25 तक पूरा करने का लक्ष्य
- 1 लाख किलोमीटर के राजमार्गों की संख्या को दोगुना करना
- वर्ष 2024-25 तक 35 लाख किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर बिछाना
- देश की प्रमुख नदियों की माल ढुलाई क्षमता को बढ़ाना
- रेलवे की कार्गो क्षमता को 1200 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 1600 मीट्रिक टन करना

पी.एम. डिवाइन योजना

- पूरा नाम : पूर्वोत्तर के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल
- कब : 2022
- किसने : केंद्रीय वित्त मंत्रालय
- प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का ही एक प्रारूप

MKLIVE

- पूर्वोत्तर की सभी विकास परियोजनाओं के लिए समग्र एवं एकीकृत योजना

राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम

- कब : 2022
- किसने : केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा बजटीय भाषण में घोषणा
- भारत सरकार के 100% स्वामित्व वाली इकाई के रूप में स्थापित
- प्रारंभिक शेयर पूंजी 5,000 करोड़ रुपए
- उद्देश्य : सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं की भूमि और गैर-प्रमुख संपत्तियों के मुद्रीकरण में तेज़ी लाना
- वस्तुतः कई केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पास भूमि और भवन जैसी अतिरिक्त परिसंपत्तियां है, जिन्हें उत्पादन हेतु प्रयुक्त नहीं किया जा रहा है। यह निगम इस प्रकार की परिसंपत्तियों का मौद्रिक मूल्य निर्धारित करेगा।
- इस मुद्रीकरण आकलन के आधार पर निकट भविष्य में इन अप्रयुक्त संपत्तियों का उपयोग निजी क्षेत्र से निवेश आकर्षित करने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए किया जा सकेगा। साथ ही इस प्रकार की परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण से सरकार को अतिरिक्त राजस्व की भी प्राप्ति होगी, जिसका प्रयोग आधारभूत ढांचे के विकास में किया जा सकेगा।

'ऊपरी भद्रा परियोजना'

- 2022 में केंद्र सरकार द्वारा 'ऊपरी भद्रा परियोजना' (Upper Bhadra Project) को 'राष्ट्रीय परियोजना' का दर्ज़ा
- राष्ट्रीय दर्ज़ा प्राप्त करने वाली कर्नाटक की पहली परियोजना
- इससे इस परियोजना को केंद्र से लगभग 60% वित्तीय सहयोग प्राप्त होगा।
- राष्ट्रीय दर्ज़ा प्राप्त करने वाली यह कर्नाटक की पहली परियोजना

ऊपरी भद्रा परियोजना

चित्रदुर्ग, चिक्कमगलुरू, दावणगेरे और तुमकुरु के सूखाग्रस्त ज़िलों में ख़रीफ़ मौसम में स्थायी सिंचाई सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू

तुंगभद्रा नदी

- कर्नाटक & आंध्र प्रदेश में
- नदी का प्राचीन नाम : पम्पा
- लगभग 710 किमी. लंबी
- दो नदियों तुंगा और भद्रा का संगम
- तुंगा और भद्रा दोनों नदियाँ पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों से निकलती हैं।
- नदी मुख्य रूप से वर्षा द्वारा पोषित
- प्रमुख सहायक नदियाँ : भद्रा, हरिद्रा, वेदवती, तुंगा, वरदा और कुमदावती
- पूर्वी कृष्णा नदी में मिलने से पहले यह कमोबेश उत्तर-पश्चिम दिशा में बहती है।
- कृष्णा नदी अंत में बंगाल की खाड़ी में मिलती है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला **2.0** योजना

- 2021 में केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का शुभारंभ
- लक्ष्य : 1 करोड़ लोगों के साथ ही 50 जिलों के 21 लाख घरों में निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करने

दूसरा चरण पहले चरण से कैसे अलग **?**

- दूसरे चरण के तहत मुख्यतः उन लोगों को लक्षित किया गया है जो रोजगार अथवा अन्य किसी कारण से अपने मूल स्थान के बजाय किसी अन्य स्थान पर रहते हैं और रसोई गैस का कनेक्शन लेने में कठिनाई आती है।
- दूसरे चरण में गरीबी रेखा की शर्त समाप्त और देश के हर घर में रसोई गैस कनेक्शन की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना **1.0**

MKLIVE

- कब : 2016
- केंद्रीय पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय
- उद्देश्य : गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों को निशुल्क रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना
- विशेष : महिला के नाम पर रसोई गैस कनेक्शन
- योजना के पहले चरण के तहत 5 करोड़ बीपीएल परिवारों की महिला सदस्यों को निशुल्क एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था।
- वर्ष 2018 में 5 करोड़ के बजाय 8 करोड़ के लक्ष्य को निर्धारित किया गया और इसे वर्ष 2019 में प्राप्त कर लिया गया।
- संयुक्त राष्ट्र ने भारत की इस योजना को वैश्विक स्तर पर सबसे सफलतम योजनाओं में से एक माना है।

उजाला **(UJALA)** योजना को **8** वर्ष पूरे

- Unnat Jyoti by Affordable LEDs for All
- कब : 5 जनवरी, 2015
- किसने : केंद्रीय विद्युत मंत्रालय
- नोडल एजेंसी : Energy Efficiency Services Limited (EESL)
- उद्देश्य : कम लागत पर LED बल्ब उपलब्ध कराकर ऊर्जा बचत और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना
- विद्युतीकरण के उद्देश्य से चलाई गई विश्व की सबसे बड़ी घरेलू योजना
- योजना में पूर्णत: स्वदेशी (घरेलू) तकनीकी का प्रयोग
- प्रतिवर्ष लगभग 50 बिलियन किलोवाट ऊर्जा की बचत

ग्राम उजाला योजना

- कब : 2021
- केंद्रीय विद्युत मंत्रालय
- नोडल एजेंसी : Energy Efficiency Services Limited (EESL)

MKLIVE

- उद्देश्य : ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे सस्ता एलईडी बल्ब प्रदान करने की योजना
- कार्बन क्रेडिट के आधार पर वित्त-पोषित योजना

योजना का महत्व

- ग्रामीण रोजगार के साथ-साथ स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा
- जलवायु परिवर्तन से निपटने में सहायक
- LED बल्ब ऊर्जा बचाने में सहायक
- CO2 उत्सर्जन में कमी

राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना

- कब : 2021
- किसने : नीति आयोग
- योजना की अवधि : वर्ष 2025
- उद्देश्य : नया बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए निजी क्षेत्र से निवेश आकर्षित करना
- लक्ष्य : सरकारी परिसंपत्तियों को लीज पर देकर अगले चार वर्षों के भीतर छह लाख करोड़ रूपए की आय अर्जित करना
- योजना के तहत कम प्रयोग में आने वाली संपत्तियों को लीज या किराए पर दी जाएंगी
- समझौते की तय सीमा के बाद संपत्ति सरकार को वापस सौंप दी जाएगी।
- केवल केंद्र सरकार के मंत्रालयों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संपत्ति ही सम्मिलित
- योजना के तहत केवल ब्राउनफील्ड परियोजनाएं सम्मिलित
- सरकार सरकारी संपत्ति नहीं बेचेगी और न ही निजीकरण करेगी, सरकार का स्वामित्व बना रहेगा।
- सरकार का लक्ष्य अगले 4 वर्षों में इस प्रकार से 6 लाख करोड़ रुपए जुटाना
- इससे प्राप्त राशि को अन्य विकास कार्यों में खर्च किया जाएगा।

MKLIVE

इस कार्यक्रम का रणनीतिक उद्देश्य संस्थागत और दीर्घकालिक पूंजी का उपयोग करके सार्वजनिक क्षेत्र की मौजूदा (ब्राउनफील्ड) परिसंपत्तियों में निवेश को हासिल करना है, जिसे आगे सार्वजनिक निवेश के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह से निवेश को हासिल करने के तौर-तरीकों पर विशेष जोर दिया, जिसे निजीकरण या औने-पौने मूल्यों पर परिसंपत्तियों को बेचने के बजाय व्यवस्थित अनुबंधात्मक साझेदारी के जरिए प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है।

उपाध्यक्ष, नीति आयोग

EASE 4.0

- कब : जुलाई, 2021
- केंद्रीय वित्त मंत्रालय
- उद्देश्य : सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन का आकलन करना;
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कार्यप्रणाली एवं प्रभावशीलता में सुधार;
- स्वच्छ और स्मार्ट संस्थागत बैंकिंग

EASE 4.0 के तहत प्रस्तावित विषय

- 24x7 बैंकिंग
- उत्तर-पूर्वी राज्यों के बैंकों पर फोकस
- बैड बैंक
- 'एक जिला, एक निर्यात' एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिये बैंकों से राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करने का आग्रह
- EASE 1.0 : सार्वजनिक बैंकों के NPA में सुधार लाना (2018)
- EASE 2.0 : वित्तीय समावेशन, ज़िम्मेदार बैंकिंग, ग्राहक फीडबैक (2019)
- EASE 3.0 : सभी ग्राहकों के लिए बैंकिंग व्यवस्था को सरल बनाना (2020)

MKLIVE

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को जारी रखने की अनुमति

- केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को वर्ष 2026 तक जारी रखने की अनुमति
- विशेष क्यों : क्योंकि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति के तहत पूर्ववर्ती सभी शिक्षा योजनाओं को समाहित करने की घोषणा
- किंतु राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जारी रहेगा

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान

- कब : 2013
- किसने : तत्कालीन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय
- वित्त पोषण : 65ः35 तथा पूर्वोत्तर के लिए 90ः10
- उद्देश्य : उच्चतर शिक्षा में समता, पहुंच और उत्कृष्टता का समावेश करना

समर्थ अभियान

- कब : 7 मार्च, 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला के दिवस पर
- केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय
- उद्देश्य : महिला उद्यमशीलता & स्वरोजगार को बढ़ावा देना
- समर्थ पहल के अंतर्गत मंत्रालय की कौशल विकास योजनाओं के अंतर्गत आयोजित मुफ्त कौशल विकास कार्यक्रमों में 20% सीटें महिलाओं के लिए

कौशल्या मातृत्व योजना

- कब : मार्च, 2022
- किसने : छत्तीसगढ़ सरकार
- उद्देश्य : बाल लिंगानुपात के स्तर में सुधार लाना
- दूसरी बेटी का जन्म होने पर महिला को एकमुश्त 5 हजार रुपये

स्त्री मनोरक्षा परियोजना

- कब : मार्च, 2022

- किसने : केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- उद्देश्य ⇒ वन स्टॉप सेंटरों के माध्यम से महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करना

'झरोखा' उत्सव

- कब : 8 मार्च, 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर
- कहां : भोपाल में आयोजित
- किसने : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं मध्यप्रदेश सरकार द्वारा
- उद्देश्य : पारंपरिक भारतीय हस्तशिल्प, हथकरघा और कला एवं संस्कृति का उत्सव में महिलाओं की भूमिका का स्मरण करना और प्रोत्साहित करना
- अपनी तरह का पहला कार्यक्रम जो कला क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को समर्पित

पीएम-दक्ष योजना

- कब : 2021 : 'पीएम-दक्ष' पोर्टल और 'पीएम-दक्ष' मोबाइल एप्प
- किसने : सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- NeGD (National E-Governance Division) के सहयोग से पोर्टल विकसित
- उद्देश्य : SC, ST, पिछड़ा वर्ग और सफाई कर्मचारियों के लिए कौशल विकास योजनाओं को सुलभ बनाना

रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब

- कब : 2022
- किसने : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)
- कहां : बेंगलुरु
- कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत RBI की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी
- प्रारंभिक पूंजी : 100 करोड़ रुपए

MKLIVE

- उद्देश्य : वित्तीय समावेशन
- हब के पास एक स्वतंत्र बोर्ड & अध्यक्ष : गोपालकृष्णन
- एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र निर्मित करना, जो देश में कम आय वाली जनसंख्या के लिए वित्तीय सेवाओं और उत्पादों तक पहुंच को बढ़ावा देने पर केंद्रित हो

H2Ooooh! पहल

- कब : 22 मार्च (2022) को विश्व जल दिवस के अवसर
- किसने : यूनेस्को
- उद्देश्य : बच्चों (6 से 16 वर्ष की आयु) में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता
- पर्यावरण की सुरक्षा हेतु छात्रों को अपने स्वयं के अनुभव और प्रस्तावों को साझा करने में सक्षम बनाना

स्माइल योजना

- कब : 2022
- किसने : केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- वर्ष 2021 में केवल भिक्षावृत्ति में संलग्न लोगों के लिए प्रारंभ; किंतु नवीनीकृत योजना में ट्रांसजेंडर समुदाय भी सम्मिलित
- उद्देश्य : पुनर्वास के साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कानूनी सहायता
- 2021 में इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 7 शहरों (दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, इंदौर, लखनऊ, नागपुर, पटना) में
- किंतु 2022 में योजना का दायरा राष्ट्रीय स्तर पर

जेट जीरो

- कब : 2022
- किसने : यूनाइटेड किंगडम
- उद्देश्य : हवाई यात्रा से होने वाले कार्बन अथवा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को पूरी तरह समाप्त करना

MKLIVE

- लक्ष्य : वर्ष 2050 तक अपने देश को पूर्णतः कार्बन उत्सर्जन से मुक्त करना
- जेट जीरो योजना इसी लक्ष्य का एक भाग

'ऑपरेशन आहट'

- कब : फरवरी, 2022
- किसने : रेलवे सुरक्षा बल (RPF)
- उद्देश्य : मानव तस्करी को रोकने हेतु एक राष्ट्रव्यापी अभियान
- सभी लंबी दूरी की ट्रेन मार्गों पर विशेष टीमों को तैनात किया जाएगा, जो महिलाओं और बच्चों को तस्करों के चंगुल से बचाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

पर्वतमाला योजना

- कब : 2022
- किसने : केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
- उद्देश्य : पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार + पर्यटन को बढ़ावा + यात्रियों हेतु सुविधा में सुधार
- PPP मोड में क्रियान्वित

मिशन इंद्रधनुष **4.0**

- 2022 में राजस्थान के जयपुर से प्रारंभ
- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
- उद्देश्य : 2 वर्ष तक के बच्चों को 9 तरह की बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण अभियान (BCG, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, पेंटावेलेंट, FIPV, RVV, PCV, MR, TD)
- उन्हीं बच्चों को सम्मिलित, जो नियमित टीकाकरण से किसी कारणवश वंचित

मिशन इंद्रधनुष **2.0**

MKLIVE

- कब शुरू : जनवरी, 2020
- संबंधित मंत्रालय : केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
- लक्ष्य : 7 रोगों के संदर्भ में पूर्ण टीकाकरण
- लक्षित वर्ष : निर्धारित नहीं

मिशन इन्द्रधनुष **1.0**

- कब शुरू : 2014
- संबंधित मंत्रालय : केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
- लक्ष्य : 7 रोगों के संदर्भ में पूर्ण टीकाकरण
- लक्षित वर्ष : 2020

देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र

- कब : फरवरी, 2022
- कहां : केरल के त्रिशूर में
- किसने : केंद्रीय विज्ञान मंत्रालय का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
- टाटा स्टील इस केंद्र के लिए औद्योगिक भागीदार
- उद्देश्य : ग्राफीन के संदर्भ में अनुसंधान एवं विकास कार्यों को बढ़ावा देना

राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति**, 2022**

- कब : 2022
- किसने : केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
- उद्देश्य : ग्रीन हाउस गैस (GHG) उत्सर्जन को 15-25% तक कम करना + भारत के तेल, गैस और कोयले के आयात को कम कर भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करना

नीति के प्रमुख बिंदु

- वर्ष 2030 तक 5 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने का लक्ष्य

MKLIVE

- हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया निर्माता किसी भी पावर एक्सचेंज से अक्षय ऊर्जा खरीद सकते हैं अथवा स्वयं अक्षय ऊर्जा इकाई स्थापित कर सकते हैं।
- हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया निर्माता अपनी अप्रयुक्त अक्षय ऊर्जा को 30 दिनों तक वितरण कंपनी (डिस्कॉम) के पास जमा कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर इसे वापस प्राप्त कर सकते हैं।
- डिस्कॉम लाइसेंसधारी अपने राज्यों में हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया के निर्माताओं को रियायती कीमतों पर अक्षय ऊर्जा की खरीद एवं आपूर्ति कर सकते हैं।
- हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया के निर्माताओं को निर्यात या शिपिंग द्वारा उपयोग के लिये हरित अमोनिया के भंडारण हेतु बंदरगाहों के पास बंकर स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी।
- इसके लिये भूमि, संबंधित पत्तन प्राधिकरणों द्वारा लागू शुल्क पर उपलब्ध कराई जाएगी।
- नीति में पौधों से हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से मंज़ूरी दी जाएगी।
- इस प्रकार हाइड्रोजन और अमोनिया भविष्य में जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करेंगे।
- नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा व्यापार सुगमता सुनिश्चित करने हेतु एकल पोर्टल स्थापित किया जाएगा।

श्रेष्ठ योजना

- कब : 2022
- किसने : केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
- उद्देश्य : अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित निजी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करके उनका समग्र विकास करना

MKLIVE

- योजना के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में नीति आयोग द्वारा चिन्हित ज़िलों में अनुसूचित जाति के कक्षा 9वीं से 12वीं तक मेधावी छात्रों को शिक्षा दी जाएगी।

सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची

- कब : 2021; जनवरी, 2022 में पुनः संशोधित
- किसने : रक्षा मंत्रालय
- उद्देश्य : रक्षा विनिर्माण में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना
- इस सूची में सम्मिलित किए जाने वाले उपकरणों के विदेशी आयात पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है ताकि इस संदर्भ में घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सके।
- SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार भारत सैन्य क्षेत्र में अमेरिका और चीन के बाद सबसे अधिक खर्च करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश हैं।

'पढ़े भारत अभियान'

- 100 दिवसीय पठन-पाठन अभियान
- कब : 1 जनवरी से 10 अप्रैल तक (2022)
- किसने : केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय
- उद्देश्य : स्थानीय, जनजातीय भाषा & मातृभाषा में पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करके पठन-पाठन संस्कृति को बढ़ावा देना

फ्लाई ऐश मैनेजमेंट एंड यूटिलाइज़ेशन मिशन

- 2022 में फ्लाई ऐश मैनेजमेंट एंड यूटिलाइज़ेशन मिशन का गठन करने का एनजीटी का निर्देश
- सरकार को फ्लाई ऐश मैनेजमेंट एंड यूटिलाइज़ेशन मिशन का गठन करना चाहिए, जिससे फ्लाई ऐश का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जा सके।

मिशन के कार्य अथवा उद्देश्य

MKLIVE

- फ्लाई ऐश और इससे संबंधित मुद्दों के प्रबंधन तथा निपटान हेतु समन्वय एवं निगरानी करना
- फ्लाई ऐश के वार्षिक स्टॉक के निपटान की निगरानी करना

मिशन का नेतृत्व

- संयुक्त रूप से केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय कोयला और बिजली मंत्रालय के सचिव तथा मिशन से संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों के द्वारा
- केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय का सचिवालय नोडल एजेंसी

फ्लाई ऐश **?**

- कोयला संयंत्रों से मुक्त होने वाला एक प्रकार का अवशिष्ट/प्रदूषक
- सीमेंट ईंट सड़क जैसी निर्माणकारी गतिविधियों में इस्तेमाल
- सीसा, क्रोमियम, मैग्नीशियम, जस्ता, आर्सेनिक आदि प्रदूषक
- वर्तमान में लगभग 63 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग
- भविष्य में इसे बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने का लक्ष्य

ऐश ट्रैक

- कब : 2018
- किसने : केंद्रीय विद्युत मंत्रालय
- उद्देश्य : फ्लाई ऐश का उचित प्रबंधन + निर्माण कार्यों में प्रयोग करना

वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम

- कब : दिसंबर, 2021
- किसने : नीति आयोग
- उद्देश्य : देश भर में नवोन्मेषकों और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए
- यह कार्यक्रम देश के नवोन्मेषकों और उद्यमियों को आठवीं अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषाओं में नवाचार पारितंत्र तक पहुँच प्रदान करेगा।

MKLIVE

- यह कार्यक्रम भाषा की बाधाओं को दूर करने और देश के दूरस्थ क्षेत्रों में नवोन्मेषकों को सशक्त बनाने में सहायक होगा।
- युवाओं में संज्ञानात्मक (cognitive) एवं डिजाइन से संबंधित सोच को मजबूत करेगा।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

- दिसंबर, 2021 में केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2026 तक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के विस्तार को मंज़ूरी
- कब : 2015
- किसने : केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
- किसानों को सिंचाई उपकरणों पर सब्सिडी प्रदान करने की योजना
- केंद्र एवं राज्यों की 75: 25 की भागीदारी पर आधारित
- उद्देश्य : हर खेत को पानी

लक्ष्य

- गैर-सिंचित कृषि भूमि को सिंचित कृषि भूमि में परिवर्तित करना
- अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के साथ ही किसानों की आय में वृद्धि करना
- जल संरक्षण एवं भू-जल स्तर में भी वृद्धि करना
- योजना का लाभ उन सभी छोटे एवं सीमांत किसानों को जिनके नाम कृषि भूमि

ग्लोबल गेटवे योजना

- कब : 2021
- किसने : यूरोपीय यूनियन
- उद्देश्य : वर्ष 2027 तक दुनियाभर में सार्वजनिक और निजी बुनियादी ढांचे में निवेश हेतु 300 अरब यूरो (EURO 300 billion) जुटाना

- हालांकि आधिकारिक तौर पर स्पष्ट नहीं कि फंड किस प्रकार जुटाया जाएगा ?

Perform, Achieve and Trade (PAT) योजना

- 2022 में विज्ञान और पर्यावरण केंद्र (Center for Science and Environment) द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अंतर्गत प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (Perform, Achieve and Trade) योजना के दोषपूर्ण क्रियान्वयन को प्रकट किया गया।

Perform, Achieve and Trade योजना

- कब : 2008
- किसने : केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय
- उद्देश्य : भारतीय उद्योगों की ऊर्जा दक्षता में सुधार लाना + ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना

PAT में सम्मिलित ऊर्जा गहन क्षेत्र

- थर्मल पावर प्लांट, सीमेंट, एल्यूमीनियम, लोहा और इस्पात
- कागज़, उर्वरक, क्लोर-क्षार, पेट्रोलियम रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल्स
- वितरण कंपनियाँ, रेलवे, कपड़ा एवं वाणिज्यिक भवन (होटल व हवाई अड्डे)
- PAT संवर्द्धित ऊर्जा दक्षता पर राष्ट्रीय मिशन (National Mission for Enhanced Energy Efficiency) का हिस्सा, जो जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (National Action Plan on Climate Change) के मिशनों में से एक है।

जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य-योजना

- कब : 2008
- किसने : केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय

MKLIVE

- उद्देश्य : राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन संबंधी खतरों से जागरूकता उत्पन्न करना
- योजना के तहत मूलतः 8 लक्ष्य स्वीकृत

1. संवर्द्धित ऊर्जा दक्षता पर राष्ट्रीय मिशन
2. राष्ट्रीय सौर मिशन
3. सुस्थिर निवास पर राष्ट्रीय मिशन
4. राष्ट्रीय जल मिशन
5. सुस्थिर हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन
6. हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन
7. सुस्थिर कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन
8. जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन

विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना

- कब : 2021
- किसने : केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
- क्या : SC & ST के उद्योगों द्वारा के लिए उन्नत तकनीक, मशीनों तथा सेवा उपकरणों की खरीद के लिए 25% की सब्सिडी
- उद्देश्य : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों में नवाचार तथा प्रौद्योगिकी का समावेश करना, ताकि उत्पादन में वृद्धि करते हुए अर्थव्यवस्था को गतिशीलता प्रदान की जा सके।

'दुआरे राशन' योजना

- कब : नवंबर, 2021
- किसने : पश्चिम बंगाल
- उद्देश्य : सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से घर तक राशन की उपलब्धता सुनिश्चित करना
- इस हेतु राज्य सरकार द्वारा 'खाद्य साथी : अमर राशन' मोबाइल एप भी लाँच

ओ-स्मार्ट योजना

- कब : 2021
- किसने : पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- उद्देश्य : समुद्री अनुसंधान को बढ़ावा देना और पूर्व चेतावनी मौसम प्रणाली स्थापित करना

पोषण स्मार्ट गांव

- कब : नवंबर, 2021
- किसने : केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
- उद्देश्य : गांवों में राष्ट्रीय पोषण अभियान को मजबूती प्रदान करना
- इस के तहत गांवों को निजी एवं विभिन्न सार्वजनिक इकाईयों द्वारा गोद लिया जाएगा और उन गांवों में कुपोषण की समस्या को दूर करने के साथ ही कृषि सुधार कार्यक्रमों की भी रूपरेखा निर्मित की जाएगी।
- इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण संबंधी जागरूकता, शिक्षा एवं व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना है, जिसमें कृषि कार्य करने वाली महिलाओं एवं विद्यालय जाने वाले बच्चों को सम्मिलित किया जाएगा।

भारतीय अंतरिक्ष संघ की स्थापना

- कब : 2021
- निजी संस्थानों का एक औद्योगिक निकाय है, जो भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में तकनीक का प्रसार बढ़ाएगा।
- संस्थापक सदस्य : भारती एयरटेल, लार्सन एंड टूब्रो, नेल्को (टाटा ग्रुप) वनवेब, मैप माय इंडिया, वालचंदनगर इंडस्ट्रीज और अनंत टेक्नोलॉजी लिमिटेड जैसी प्रमुख निजी कंपनियां

'SACRED' पोर्टल

- कब : 1 अक्टूबर, 2021 को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर लांच

- किसने : केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
- उद्देश्य : वृद्ध नागरिकों को रोजगार के अवसर प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन

- कब : 2021
- किसने : केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- नोडल एजेंसी : राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण
- उद्देश्य ⇒ सभी भारतीय नागरिकों को अस्पतालों, बीमा कंपनियों और आवश्यकता पड़ने पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुँचने में सहायता करने के लिये डिजिटल स्वास्थ्य ID प्रदान करना
- वस्तुतः यह आयुष्मान भारत योजना का एक डिजिटल मोड है, जिसका मूल उद्देश्य नागरिकों के स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों को आनलाइन माध्यम से संग्रहित करना है।
- मिशन के तहत प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य ID प्रदान की जाएगी, जो एक प्रकार से उनके स्वास्थ्य खाते के रूप में कार्य करेगी।
- इस स्वास्थ्य खाते में परीक्षण, बीमारी, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट, ली गई दवाओं और इत्यादि के बारे में समस्त जानकारी रहेगी।

My Port ऐप

- कब : 2021
- किसने : केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय
- पोर्ट संचालन की डिजिटल निगरानी के लिए लांच
- उद्देश्य : पारदर्शिता को बढ़ावा देना और बंदरगाह से संबंधित जानकारी प्रदान करना
- ऐप में बंदरगाह के बारे में सभी तथ्य डिजिटल रूप से सम्मिलित

Tax Inspectors Without Borders Programme

- कब : 2021
- किसने : संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) तथा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD)
- भारत इस कार्यक्रम के लिये भागीदार प्रशासन के रूप में चुना गया है
- उद्देश्य : अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर भुगतान प्रणाली को मजबूती एवं पारदर्शिता प्रदान करना

i-Drone

- कब : 2021
- किसने : केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
- भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) द्वारा विकसित
- उद्देश्य : कठिन और दुर्गम इलाकों में ड्रोन-आधारित वैक्सीन डिलीवरी

High Ambition Coalition for Nature and People (HAC)

- कब : 2019
- किसने : कोस्टारिका, फ्रांस और ब्रिटेन
- प्रकृति : एक अंतर सरकारी समूह
- सदस्य : 72
- उद्देश्य : वैश्विक 30×30 लक्ष्य

वैश्विक **30×30** लक्ष्य

- 2030 तक दुनिया की कम से कम 30% भूमि और महासागर की रक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते को बढ़ावा देना
- 2021 में भारत 'हाई एम्बिशन कोएलिशन फॉर नेचर एंड पीपल' (HAC) में सम्मिलित
- भारत HAC में सम्मिलित होने वाला पहला ब्रिक्स देश

केंद्र सरकार की **60** सूत्री योजना **!**

MKLIVE

- 2021 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारियों की हुई बैठक में 60 सूत्री योजना की रूपरेखा पर चर्चा
- हालांकि इस योजना के संबंध में औपचारिक रूप से अभी कोई घोषणा नहीं

क्या है **60** सूत्री योजना **?**

- वस्तुतः इस योजना के तहत डेटा के अधिकतम कुशल प्रयोग पर मुख्य रूप से बल दिया जाएगा।
- डेटा के अधिकतम उपयोग के लिए मुख्यतः तीन क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है जिसमें शासन प्रणाली, आर्थिक गतिविधियों एवं सिविल सेवाओं में सुधार करना सम्मिलित है।
- योजना के प्रारंभिक चरण में केंद्र सरकार का उद्देश्य इन तीनों क्षेत्रों के 60 लक्ष्यों अथवा विषयों को चिन्हित किया जाएगा।

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड

- कब : 2015
- किसने : केंद्रीय वित्त मंत्रालय
- योजना के तहत न्यूनतम एक ग्राम और अधिकतम 500 ग्राम सोने के मूल्य के बराबर बॉण्ड ख़रीदे जा सकते हैं।
- स्वर्ण बॉण्ड 'सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006' के तहत भारत सरकार के स्टॉक के रूप में RBI द्वारा जारी
- बॉण्ड की परिपक्वता अवधि 8 वर्ष & पांचवें, छठे अथवा सातवें वर्ष में इससे बाहर निकलने का विकल्प
- ब्याज की दर 2.5%
- बॉण्ड का उपयोग ऋण के लिए गारंटी के रूप में किया जा सकता है।
- आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार गोल्ड बॉण्ड पर प्राप्त होने वाले ब्याज पर कर अदा करना होता है, हालांकि पूंजीगत लाभ कर मुक्त कर है।
- योजना के तहत बैंकों द्वारा प्राप्त किए गए बॉन्डों की गिनती वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) के संदर्भ में की जाती है।

MKLIVE

उद्देश्य

- मंदिरों तथा घरों में जमा गोल्ड की विशाल मात्रा को उत्पादक कार्यों में लगाना
- सोने का आयात कम करना
- विदेशी मुद्रा का संरक्षण करना
- चालू खाता घाटे को कम करना

मैं भी डिजिटल अभियान **3.0**

- कब : 2021
- किसने : केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय IT मंत्रालय के सहयोग से
- PM स्वनिधि योजना के तहत लांच
- उद्देश्य : स्ट्रीट वेंडर्स को ऑनलाइन भुगतान लेने में सक्षम बनाना
- अभियान के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को UPI के माध्यम से भुगतान लेने के संबंध में प्रशिक्षित किया गया

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि **: PM** स्वनिधि

- कब : 2020
- किसने : केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय
- स्ट्रीट वेंडर्स को अधिकतम 10 हजार रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराना
- बिना किसी गारंटी के ऋण अर्थात् Unsecured Loan
- स्कीम के तहत सरकार द्वारा 5000 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत

स्ट्रीट वेंडर्स → स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम**, 2014**

जिन लोगों के पास स्थायी दुकान नहीं है + जो किसी सार्वजनिक या निजी स्थान पर बने अस्थायी ढांचे से या जगह-जगह घूम कर आम जनता के लिए रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुओं या सेवाओं की पेशकश करता है।

देश में कुल शहरी अनौपचारिक रोज़गार (गैर-कृषि) में 14% स्ट्रीट वेंडर्स

‘तपस’ पोर्टल **/ TAPAS Portal**

MKLIVE

- कब : 2021
- केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
- राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान द्वारा विकसित
- उद्देश्य : क्षमता निर्माण करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना + ज्ञान एवं कौशल का विकास करना

पोर्टल **5** प्रमुख विषयों पर केंद्रित

1. सामाजिक रक्षा विषयों पर 4 पाठ्यक्रम
2. नशीली दवाओं (पदार्थ) के दुर्व्यवहार की रोकथाम
3. बुजुर्ग लोगों की देखभाल
4. डिमेंशिया पीड़ित लोगों की देखभाल
5. ट्रांसजेंडर

'आयुष आपके द्वार'

- कब : अक्टूबर, 2021
- किसने : केंद्रीय आयुष मंत्रालय
- एक वर्ष में देश के 75 लाख घरों में औषधीय पौधे वितरित करने का अभियान;
- ताकि भारतीय आयुर्वेद की परंपरा को पुनर्जीवित करने के साथ ही पौधों के औषधीय महत्व को समझा जा सके

संसदीय आउटरीच कार्यक्रम

- कब : 2021
- किसने : लोकसभा
- उद्देश्य : स्थानीय जनता में संसदीय कार्यप्रणाली के प्रति जागरूकता विकसित करना

संसद सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था है और पंचायत स्तर सहित सभी स्तरों पर लोकतंत्र को मज़बूत करना संसद का उत्तरदायित्व है। यह अपनी तरह का पहला

MKLIVE

कार्यक्रम है, जो ज़मीनी स्तर पर शासन एवं नियोजन संस्था को मज़बूत करने का प्रयास करता है।

लोकसभा अध्यक्ष

'साथ' पहल

- कब : 2021
- किसने : जम्मू-कश्मीर सरकार
- उद्देश्य : स्वयं सहायता समूहों की भूमिका के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं की आजीविका के अवसरों का सृजन करना
- ग्रामीण महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों के लिए बाजार की सुविधा प्रदान करने पर केंद्रित पहल

'प्रसाद' योजना

- महत्त्वपूर्ण तीर्थ और विरासत स्थलों का कायाकल्प एवं आध्यात्मिक संवर्द्धन
- कब : 2014
- किसने : केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय
- केंद्र द्वारा शत-प्रतिशत वित्त पोषित योजना
- PPP और CSR की अवधारणा पर भी आधारित

उद्देश्य

- पर्यटन
- आधारभूत संरचना
- आध्यात्मिक विकास
- भारतीय विरासत एवं ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण
- 2021 में इस योजना में सोमनाथ मंदिर सम्मिलित

सोमनाथ मंदिर

- गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में स्थित

MKLIVE

- अन्य नाम : देव पाटन मंदिर
- भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला मंदिर
- ऋग्वेद में चंद्रदेव द्वारा निर्मित कराए जाने का उल्लेख
- समय-समय पर विदेशी आक्रमण
- महमूद गजनवी द्वारा 1025 ई. में किया गया आक्रमण सबसे प्रमुख
- स्वतंत्रता के बाद सरदार पटेल की मंदिर के पुनर्निर्माण में उल्लेखनीय भूमिका
- मूलतः नागर शैली पर आधारित मंदिर, किंतु चालुक्य शैली में पुनर्निर्माण
- मंदिर गर्भगृह, सभामंडप और नृत्यमंडप तीन प्रमुख भागों में विभाजित

'धरोहर गोद लो' परियोजना

- कब : 2017
- अन्य नाम : विरासत अंगीकरण परियोजना
- किसने : केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की एक संयुक्त पहल
- उद्देश्य : देश के प्राकृतिक, पर्यटन, संस्कृति एवं विरासत से संबंधित महत्वपूर्ण स्थलों में पर्यटन सुविधाओं का विकास करना
- योजना के तहत निजी एवं सार्वजनिक इकाईयों को भारत के किसी भी एक ऐतिहासिक स्थल को 5 वर्ष की अवधि के लिए गोद लेने हेतु प्रेरित किया जाता है;
- ताकि वह संस्था संबंधित स्थल में आधारभूत सुविधाओं के विकास के साथ ही उसका उन्नयन कर सके।
- 5 वर्ष की अवधि के लिए संबंधित संस्था की गतिविधियों की निगरानी एक सरकारी कमेटी द्वारा की जाती है जिसमें संबंधित मंत्रालयों के सचिव तक के अधिकारी सम्मिलित होते हैं।
- किसी भी स्थल को गोद लेने के लिए किसी प्रकार की बोली अथवा वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जाती।

MKLIVE

- मूलतः सरकारों का प्रयास रहता है कि कंपनियों द्वारा यह दायित्व अपने CSR के तहत पूरा किया जाए।
- 2021 में इस योजना में नारायण कोटि मंदिर (उत्तराखंड) सम्मिलित

नारायण कोटि मंदिर

- लक्ष्मी और नारायण को समर्पित मंदिर
- कई मंदिरों का समूह
- पांडवों से संबंधित
- विस्तृत प्रमाणिक जानकारी का अभाव

सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम **2.0**

- भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा कि वह सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम 2.0 (G-SAP 2.0) के तहत 25,000 करोड़ रुपये की सरकारी प्रतिभूतियों की खुले बाजार में खरीद करेगा।
- इससे पूर्व G-SAP 1.0 कार्यक्रम के तहत कुल 25,000 करोड़ रुपए की राशि की सरकारी प्रतिभूतियां खरीदी गई थीं।

सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम **(G-SAP)**

- मूलतः एक व्यापक आकार का बिना शर्त 'ओपन मार्केट ऑपरेशन' (OMO)
- 'बिना शर्त' का अर्थ है कि RBI ने पहले ही प्रतिबद्धता व्यक्त की है कि वह बाज़ार की भावना के बावजूद सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदेगा।
- प्रतिभूतियों की खरीद की मात्रा रिजर्व बैंक निर्धारित करेगा।

उद्देश्य

- अर्थव्यवस्था में तरलता प्रबंधन
- स्थिर और व्यवस्थित यील्ड सुनिश्चित करना

MKTVE

- सरकारी प्रतिभूतियां खरीद कर RBI अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति करता है, जिससे यील्ड रहने के साथ ही सरकार की उधार लागत भी कम हो जाती है।

डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज **5.0**

- कब : 20201
- किसने : रक्षा मंत्रालय
- उद्देश्य : भारतीय रक्षा क्षेत्र को 'आत्मनिर्भर' बनाना & नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना
- रक्षा नवाचार संगठन (Defence Innovation Organization : DIO) द्वारा वित्त पोषित
- DIO कंपनी अधिनियम 2013 की धारा-8 के तहत पंजीकृत एक गैर-लाभकारी कंपनी
- हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) इसके दो संस्थापक सदस्य

पीएम-कुसुम

- पूरा नाम : प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान
- कब : 2019
- केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय
- उद्देश्य : किसानों को अपनी बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने और इसे ग्रिड को बेचने में सक्षम बनाना

लक्ष्य

- सिंचाई गतिविधियों के लिए दिन में बिजली का विश्वसनीय स्रोत प्रदान कर किसानों के लिये जल-सुरक्षा सुनिश्चित करना
- विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना
- सिंचाई के लिए किसानों की विद्युत सब्सिडी पर निर्भरता को कम करना

MKLIVE

- बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) का वित्तीय सशक्तिकरण करना

समृद्ध कार्यक्रम

- समृद्ध : उत्पाद, नवाचार विकास और वृद्धि
- कब : अगस्त, 2021
- किसने : केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
- कार्यान्वयन : इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत स्टार्ट-अप हब (MSH) द्वारा
- उद्देश्य : देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देना + यूनिकॉर्न को बढ़ाना

यूनिकॉर्न

- किसी भी निजी स्वामित्व वाली फर्म, जिसका बाज़ार पूंजीकरण 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक
- कम-से-कम 7,500 करोड़ रुपए का टर्नओवर वाले स्टार्टअप
- 2022 में केंद्र सरकार द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत में यूनिकॉर्न की संख्या बढ़कर 100
- भारत, अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र

ई-श्रम पोर्टल

- कब : 2021
- किसने : केंद्रीय श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय
- उद्देश्य : असंगठित कामगारों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने में मदद करना
- पोर्टल पर पंजीकरण पूर्णतः निशुल्क
- इसके तहत श्रमिकों को 12 अंकों की विशिष्ट संख्या वाला एक ई-श्रम कार्ड जारी किया जाएगा, जो उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल होने तथा लाभ प्राप्त करने में मदद करेगा।

MKLIVE

- सरकार का लक्ष्य इस पोर्टल पर 38 करोड़ असंगठित कामगारों जैसे निर्माण कार्य में संलग्न मज़दूर, प्रवासी कार्यबल, रेहड़ी-पटरी वाले तथा घरेलू कामगारों आदि को पंजीकृत करना है।

'युक्तधारा' पोर्टल लांच

- कब : अगस्त, 2021
- किसने : केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय
- इसरो तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से विकसित
- पोर्टल रिमोट सेंसिंग तथा जी.आई.एस. आधारित जानकारी का उपयोग करके मनरेगा के संबंध में योजना तैयार करने की सुविधा प्रदान करेगा।

घर पोर्टल

- कब : 2022
- किसने : राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
- उद्देश्य : बच्चों के पुनर्वास और प्रत्यावर्तन को डिजिटल रूप से ट्रैक करना
- यह पोर्टल उन बच्चों की डिजिटल ट्रैकिंग और निगरानी की अनुमति देता है जो किशोर न्याय प्रणाली में हैं तथा जिन्हें दूसरे देश, राज्य या ज़िले में वापस भेजा जाना है।

मनम पहल

- कब : 2022
- किसने : तमिलनाडु सरकार
- उद्देश्य : छात्रों को आत्महत्या करने से रोकने के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित रोगियों के सही उपचार के लिये उन्हें प्रशिक्षित करना
- यह पहल छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से संपर्क करने में मदद करेगी। इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर 14416 भी जारी किया गया है।

पर्यावरण के लिये जीवन शैली

MKLIVE

- कब : 2022
- किसने : संयुक्त राष्ट्र द्वारा गुजरात के केवडिया से
- उद्देश्य : रोजमर्रा के जीवन में पर्यावरण की सुरक्षा के लिये प्रतिबद्धता
- इस मिशन के अनुसार मानव समाज अपनी जीवनशैली में बदलाव करके पर्यावरण की रक्षा कर सकता है।
- यह अभियान पी-3 मॉडल अर्थात् प्रो प्लैनेट पीपल की अवधारणा को मजबूत करता है। यह 'लाइफ स्टाइल ऑफ द प्लेनेट, फॉर द प्लेनेट एंड बाय द प्लेनेट' के मूल सिद्धांत पर आधारित है।

हरित आयकर पहल

- कब : 2022
- किसने : आयकर विभाग
- 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर
- उद्देश्य : छोटे-छोटे वन क्षेत्रों का विस्तार करना
- यह पहल आयकर विभाग की खाली पड़ी भूमि अथवा उचित भू-प्रबंधन के माध्यम से वनारोपण पर आधारित है।
- इस पहल के तहत आयकर विभाग में कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा वनारोपण किया जाएगा।

शून्य अभियान

- कब : 2021
- किसने : नीति आयोग
- उद्देश्य : इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के उपयोग को बढ़ावा देकर वायु प्रदूषण को कम करना + कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करना
- भारत में इस अभियान का शुभारंभ पारंपरिक वाहनों के स्थान पर विद्युत चालित वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है जिससे कार्बन उत्सर्जन में कमी तथा पर्यावरण संरक्षण किया जा सके।

MKLIVE

- क्योंकि पारंपरिक वाहनों की तुलना में विद्युत चालित वाहन 60% तक कम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं तथा इनकी परिचालन लागत भी 75% कम होती है।

ऑपरेशन 'गियर बॉक्स'

- कब : 2022
- किसने : केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व खुफिया निदेशालय
- उद्देश्य : मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना + खुफिया तरीके से विदेशों से भारत में आने मादक पदार्थों की तस्करी की गतिविधियों पर अंकुश लगाना
- भारत विश्व के दो सबसे बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्रों गोल्डन ट्रायंगल (दक्षिण-पूर्व एशिया) और गोल्डन क्रिसेंट (ईरान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान) के मध्य स्थित है।

- गोल्डेन ट्रायंगल वह क्षेत्र है जहां थाईलैंड, लाओस और म्यांमार की सीमाएं Ruak और Mekong नदियों के संगम पर मिलती हैं। इस नाम का प्रयोग सबसे पहले Central Intelligence Agency (CIA) के एजेंट्स द्वारा प्रयोग होना शुरू हुआ था जब यह क्षेत्र दुनियाभर में सबसे बड़ा ड्रग व्यापार का क्षेत्र बना चुका था।
- यह क्षेत्र Papaver somniferum के प्रमुख उत्पादक के रूप में भी जाना जाता है, जिसे अफीम के रूप में जाना जाता है, जो अंततः हेरोइन का उत्पादन करने के लिए उपयोग किया जाता है।

पीएम किसान सम्मान निधि

- कब : 2019
- किसने : केंद्रीय कृषि एवं किसान मंत्रालय
- पूर्णतः केंद्र प्रायोजित योजना
- योजना के तहत प्रत्येक वर्ष भूमिधारक किसानों को कुल 18 हजार रूपये (6,000 x 3) की वार्षिक सहायता
- यह राशि तीन समान किस्तों में सीधे बैंक खाते में
- लाभार्थियों की पहचान करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर

- योजना का प्रमुख उद्देश्य किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के साथ ही अनौपचारिक ऋण तंत्र से भी मुक्ति प्रदान करना
- भूमि की अधिकतम सीमा की कोई शर्त नहीं अर्थात् प्रत्येक किसान जिनके पास भूमि है, योजना के दायरे में सम्मिलित
- हालांकि वन निवासी, पूर्वोत्तर राज्य, झारखंड जैसे राज्यों के लिए इस नियम में छूट प्रदान की गई है, क्योंकि यह भूमि संबंधी अधिकारों में भिन्नता मिलती है।
- योजना के तहत पात्र किसानों के लिए ऋण की सुविधा भी
- इस हेतु किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी
- साथ ही जो किसान नियमित रूप से अपने ऋण का भुगतान वाले किसानों को अधिकतम 4 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर पर बैंक से पशुपालन आदि हेतु लघु अवधि के ऋण प्राप्त करने की भी सुविधा

मिशन कर्मयोगी

- पूरा नाम : मिशन कर्मयोगी : राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम
- कब शुरू : 2020
- किसने : केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय
- उद्देश्य : सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण के साथ-साथ संस्थागत क्षमता निर्माण

उद्देश्य

मिशन कर्मयोगी का मुख्य उद्देश्य भविष्य के लिए भारतीय सिविल सेवकों को तैयार करना है ताकि वे अधिक रचनात्मक, अभिनव, पेशेवर, प्रगतिशील, रचनात्मक,पारदर्शी, सक्रिय, ऊर्जावान और प्रौद्योगिकी-सक्षम बन सकें।

प्रमुख कार्य

MKLIVE

- सभी विभागों और सेवाओं के लिए वार्षिक क्षमता निर्माण योजना निर्धारित करना
- क्षमता निर्माण योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करना
- कुशल सेवा वितरण सुनिश्चित करेगा
- प्रौद्योगिकी-प्रेरित प्रशिक्षण को बढ़ावा देना

मिशन कर्मयोगी

- केंद्रीय बजट 2017-18 में प्रस्तुत
- उद्देश्य : यह सुनिश्चित करना कि सभी राजनीतिक दलों को जो पैसा मिला है वह काला धन तो नहीं है।
- अगर किसी को किसी राजनीतिक पार्टी को दान करना है तो वे SBI से बॉण्ड खरीद सकते हैं और पार्टी फंड में पैसा दे सकते हैं।

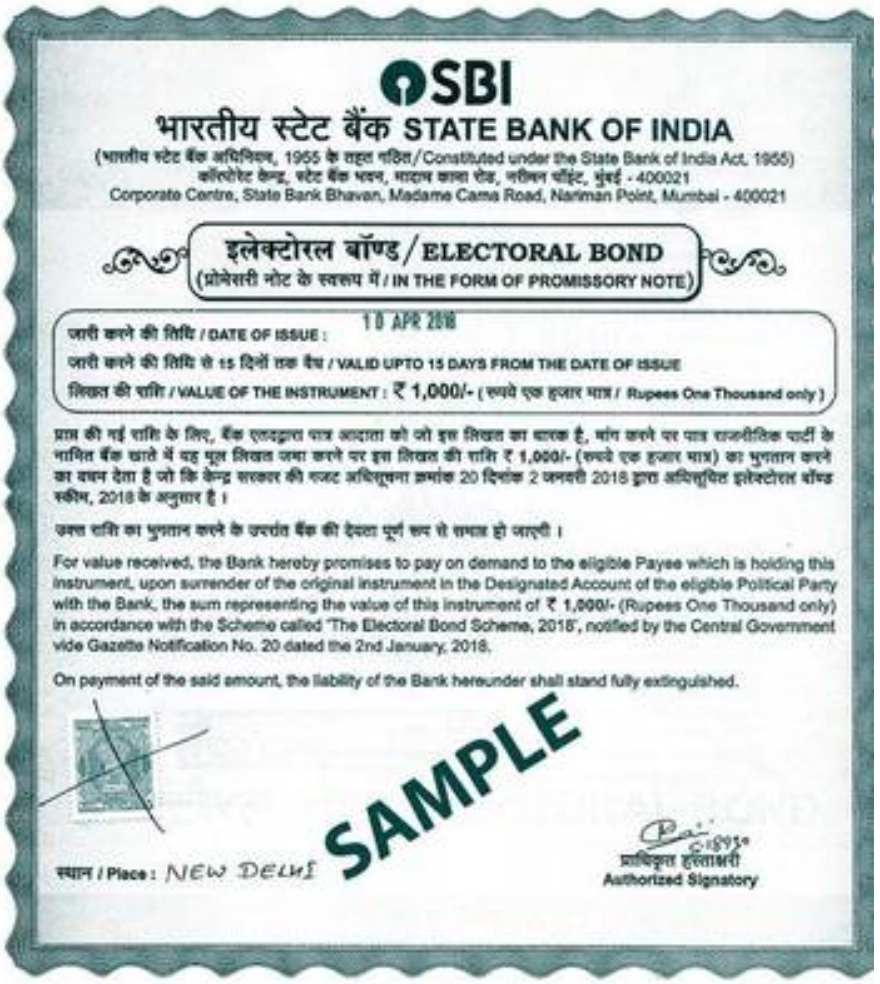

- भारत के प्रत्येक नागरिक द्वारा चुनावी बॉण्ड की खरीदारी की जा सकती है।
- किसी व्यक्ति द्वारा चुनावी बॉण्ड में निवेश की कोई सीमा नहीं है।
- चुनावी बॉण्ड में निवेश की गई राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
- जारी करने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर चुनावी बॉण्ड को भुनाना (Encashed) करना आवश्यक है।
- चुनावी बॉण्ड व्यापार योग्य नहीं होते।
- केवल वे राजनीतिक दल ही चुनावी बॉण्ड प्राप्त करने के योग्य हैं जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत पंजीकृत हैं और जिन्होंने पिछले आम चुनाव में कम-से-कम 1% मत प्राप्त किया है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि बॉण्ड के मालिक के नाम का खुलासा नहीं किया जाता है।

स्वामित्व योजना

- कब शुरू : 24 अप्रैल, 2020 को 'पंचायती राज दिवस' के अवसर पर
- किसने : केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय
- उद्देश्य : देश की ग्राम-पंचायतों और ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों को आत्मनिर्भर बनाना + साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति का रिकॉर्ड (Property Rights) बनाना और उसका मालिकाना हक तय करना
- योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की रिहायशी मकानों का लेखा-जोखा तैयार किया जाएगा।
- गाँव की सीमा के भीतर आने वाली प्रत्येक संपत्ति का डिजिटल रूप नक्शा बनाया जाएगा और प्रत्येक राजस्व खंड की सीमा का निर्धारण किया जाएगा।

कपिला अभियान

- कब शुरू : 15 अक्टूबर, 2020
- 15 अक्टूबर : डा. APJ अब्दुल कलाम का जयंती दिवस
- किसने : केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय

- उद्देश्य : बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रति जागरूकता प्रसारित करना
- इस अभियान के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों को उनके आविष्कार को पेटेंट कराने के लिये आवेदन प्रक्रिया की सही प्रणाली के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी।

One Nation One Card

- कब शुरू : 2019
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत लागू
- किसने : केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
- उद्देश्य : खाद्यान्न वितरण में सुगमता सुनिश्चित करते हुए खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य को सार्थक करना
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आने वाले लाभार्थी एक कार्ड से पूरे देश में कहीं भी राशन प्राप्त करने में सक्षम
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत सभी लोगों को अनाज की उपलब्धता

महत्व

- प्रवासी मजदूरों की खाद्य सुरक्षा, जो बेहतर रोज़गार के अवसर तलाशने में दूसरे राज्यों में जाते हैं।
- लाभार्थियों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पसंद के उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न को लेने/खरीदने का विकल्प

आयुष्मान भारत योजना / प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

- कब शुरू : 2019
- किसने : केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
- उद्देश्य : आर्थिक रूप से कमजोर लोगों (BPL धारक) को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना

MKLIVE

- इसके अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध
- लाभार्थी को देश भर के किसी भी सार्वजनिक या निजी अन्तर्गत अस्पताल से कैशलेस लाभ लेने की अनुमति
- लाभार्थी द्वारा इस योजना का लाभ पूरे देश में कहीं भी लिया जा सकता है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

- कब : 2016
- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
- फसलें : सभी खाद्यान्न, तिलहन, वाणिज्यिक तथा बागवानी फसलें
- बीमा प्रीमियम राशि : खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी की फसलों के लिए 1.5%, बागवानी फसलों के लिए 5%
- योजना न केवल खड़ी फसल बल्कि फसल पूर्व बुवाई तथा फसल कटाई के पश्चात जोखिम भी सम्मिलित

- योजना के तहत स्थानीय आपदाओं की क्षति का भी आकलन
- संभावित दावों के 25 प्रतिशत का तत्काल भुगतान ऑनलाइन माध्यम से

मनरेगा

- पूरा नाम : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
- कब शुरू : राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत 2 फरवरी, 2006
- उद्देश्य : गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के लोगों को 'काम करने का अधिकार' प्रदान करना
- योजना का वित्तपोषण : केन्द्र (90%) और राज्य (10%)
- किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य लाभ प्राप्त करने के पात्र
- यह योजना गांव के लोगों को एक वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी देती है।
- योजना के तहत आवेदन के 15 दिनों के भीतर ही आवेदक को रोज़गार उपलब्ध कराया जाता है।
- 15 दिनों के भीतर रोज़गार न मिलने की स्थिति में आवेदक को भत्ता दिये जाने का प्रावधान है।
- इस योजना के तहत पात्र व्यक्ति को 5 किलोमीटर के दायरे के भीतर ही रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
- इस योजना के लाभार्थियों में 50% श्रमिक महिलाएं होती है।
- 15 दिनों के भीतर रोज़गार न मिलने की स्थिति में आवेदक को भत्ता दिये जाने का प्रावधान है।
- इस योजना के तहत पात्र व्यक्ति को 5 किलोमीटर के दायरे के भीतर ही रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
- इस योजना के लाभार्थियों में 50% श्रमिक महिलाएं होती है।